E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(1): 87-96
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 06-11-2024
Accepted: 08-12-2024

गौतम कुमार
(शोधार्थी) राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार, भारत।

डॉ. नरेश कुमार सिंह
(सहा. प्राध्यापक), राजनीति विज्ञान विभाग, आर. एल. एस. वाई. कॉलेज, औरंगाबाद, बिहार, भारत।

Corresponding Author:
गौतम कुमार
(शोधार्थी) राजनीति विज्ञान विभाग, मगध विश्वविद्यालय बोधगया, बिहार, भारत।

बिहार के राजनीतिक में जाति

गौतम कुमार, डॉ. नरेश कुमार सिंह

DOI: https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i1b.431

सारांश
बिहार विविधताओं से संपन्न राज्य है जो बिहार के राजनीति को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| बिहार में विभिन्न प्रकार की जातियाँ है जो यहाँ के राजनीति की दशा-दिशा तय करता है| बिहार की राजनीति कुछ प्रमुख जातियों के इर्द-गिर्द घूमते रहा है| यहाँ अधिकांशत: नीतियाँ जातीय आधार पर जनता को आकर्षित करने के लिए बनाए जाते है| इस लेख का उद्देश्य यह पता लगाना है कि बिहार के जाति एवं राजनीति के अंतर्संबंधो को समझना तथा जाति आधारित राजनीति में राजनीतिक दलों, गठबंधनो एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है| साथ ही, इस तरह के राजनीति से उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है|

मूलशब्दः जाति, राजनीतिक दल, विकास, नीतियाँ, प्रतिनिधित्व|

प्रस्तावना

परिचय

ऐतिहासिक रूप से, बिहार कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, जिसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय, और मौर्य और गुप्त साम्राज्य शामिल हैं। हालाँकि, आधुनिक समय में, बिहार के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को काफी हद तक इसकी जाति संरचना और कृषि अर्थव्यवस्था द्वारा परिभाषित किया गया है।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान, बिहार 1912 तक बंगाल प्रेसीडेंसी का हिस्सा था, जब यह एक अलग प्रांत बन गया। औपनिवेशिक काल में राष्ट्रवादी आंदोलनों का उदय हुआ, जिनमें से कई में जातिगत अंतर्धाराएँ थीं। जाति-आधारित सामाजिक विभाजन औपनिवेशिक नीतियों, विशेष रूप से भूमि स्वामित्व प्रणालियों के संदर्भ में और भी बढ़ गए, जिससे निचली जाति के किसानों की कीमत पर उच्च जाति के जमींदारों (भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत और कायस्थ) को लाभ हुआ।

स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष की भी बिहार में महत्वपूर्ण उपस्थिति थी। राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, जो उच्च जाति की पृष्ठभूमि से आते थे, ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया।

उसी समय, जगदेव प्रसाद जैसे निम्न जाति के नेताओं के नेतृत्व में सामाजिक सुधार आंदोलनों ने उच्च जाति के आधिपत्य को चुनौती देना शुरू कर दिया। इस अवधि ने जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी के लिए मंच तैयार किया, जिसने स्वतंत्रता के बाद बिहार की राजनीति को आकार दिया।

स्वतंत्रता के बाद, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर शुरू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) का वर्चस्व था, जिसे बड़े पैमाने पर उच्च जातियों से समर्थन प्राप्त था। हालाँकि, 1960 के दशक के उत्तरार्ध में, कांग्रेस के प्रभुत्व में दरारें उभरने लगीं, खासकर जब हाशिए पर पड़ी जातियों और समुदायों ने अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व की माँग शुरू कर दी। राम मनोहर लोहिया जैसे लोगों के नेतृत्व में समाजवादी राजनीति के उदय ने उच्च जाति के प्रभुत्व को चुनौती दी और जाति-आधारित मुद्दों को सबसे आगे लाया।

1970 के दशक में बिहार की राजनीति की एक परिभाषित विशेषता के रूप में जाति-आधारित राजनीतिक लामबंदी का उदय हुआ। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों की शुरूआत, जिसमें सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण का प्रस्ताव था, ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया। यादव जाति (एक प्रमुख ओबीसी समूह) का प्रतिनिधित्व करने वाले लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं ने मंडल लहर का लाभ उठाते हुए यादवों, मुसलमानों और अन्य पिछड़े वर्गों का एक शक्तिशाली जाति-आधारित राजनीतिक गठबंधन बनाया। इसके परिणामस्वरूप कांग्रेस के उच्च-जाति मतदाता आधार में गिरावट आई और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) जैसी नई राजनीतिक पार्टियों का उदय हुआ, जो जाति-आधारित समर्थन पर बहुत अधिक निर्भर था।

हाल के दशकों में, जाति ने बिहार की राजनीति पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जिसमें प्रमुख पार्टियाँ जाति के आधार पर खुद को जोड़ती हैं। जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी (यू)] के नेता नीतीश कुमार ने गैर-यादव ओबीसी, खासकर अपनी खुद की कुर्मी जाति के समर्थन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया है। जातिगत गठबंधनों के साथ-साथ विकास पर उनके ध्यान ने उन्हें जातियों का एक व्यापक गठबंधन बनाने में मदद की, हालांकि जाति-आधारित संरक्षण नेटवर्क शासन की एक प्रमुख विशेषता बना हुआ है।

जाति-आधारित राजनीति से आगे बढ़ने के प्रयासों के बावजूद, जाति की पहचान बिहार के सामाजिक-राजनीतिक ताने-बाने में गहराई से समाई हुई है। राज्य में चुनावी व्यवहार जातिगत निष्ठाओं से प्रभावित होता रहता है, राजनीतिक दल अक्सर इन विभाजनों के इर्द-गिर्द अपनी रणनीति बनाते हैं। जबकि आर्थिक और विकास संबंधी मुद्दे राजनीतिक विमर्श में अधिक प्रमुख हो गए हैं, जाति बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाली एक शक्तिशाली ताकत बना हुआ है।

शोध-विधि

बिहार में विभिन्न प्रकार की जातियाँ है जो यहाँ के राजनीति की दशा-दिशा तय करता है । बिहार की राजनीति कुछ प्रमुख जातियों के इर्द-गिर्द घूमते रहा है| राजद दल यादव-मुस्लिम जाति की, जद(यू) दल कुर्मी एवं अन्य ओबीसी जातियों की तथा लोजपा दल दलित एवं वंचित वर्गों की राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है| जाति आधारित राजनीति में अक्सर सत्ताधारी दल/ गठबंधन अपने जाति विशेष के लिए लोक नीतियाँ बनाते है| इस तरह के राजनीति से जनता के सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर अलग-अलग प्रभाव पड़ता है| इस लेख का उद्देश्य इन्ही तथ्यों का ध्यान करना है|

शोध-विधि संरचना

उद्देश्य	• बिहार के जाति एवं राजनीति के अंतर्संबंधो को समझनाहै| • जाति आधारित राजनीति में राजनीतिक दलों, गठबंधनो एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण करना है| • जातिगत राजनीति से उनके सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है|
आँकड़े	यह अध्ययन मात्रात्मक एवं गुणात्मक आँकड़ों के मिश्रित विधि पर आधारित है| इसके लिए द्वितीय स्त्रोत से आँकड़े लिए गए है|
शोध-विधि	इस अध्ययन हेतु अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक विधि का उपयोग किया गया है|

चुनावी राजनीति में जातियों की भूमिका

बिहार के राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| स्वतंत्रता के पश्चात् बिहार की राजनीति में

जातिय आधारित राजनीति ने व्यापक रूप ले लिए है| विभिन जातियों की राजनीतिक दलों के उदय होने तथा राजनीतिक नेताओं को पैदा करने में केन्द्रीय भूमिका रहा है| राजनीतिक दलों एवं नेताओं की राजनीति तंत्र इन्ही जातियों के इर्द-गिर्द रहता है| बिहार के चुनावी राजनीति में जातियों की भूमिका को निम्नलिखित रूपों में देख सकते है -

1. **जाति-आधारित पार्टियाँ: आरजेडी, जेडी (यू) जैसी जाति-आधारित पार्टियों का उदय और उनका प्रभाव** - बिहार में, जाति ने हमेशा चुनावी परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, और पिछले कुछ वर्षों में, जाति-आधारित राजनीतिक पार्टियाँ केंद्रीय खिलाड़ी बन गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी(यू)] दो प्रमुख राजनीतिक पार्टियाँ हैं जिन्होंने राजनीतिक सत्ता हासिल करने और उसे बनाए रखने के लिए जाति-आधारित लामबंदी का लाभ उठाया है।

1997 में लालू प्रसाद यादव द्वारा स्थापित आरजेडी, जाति-आधारित राजनीति के साथ अपनी चुनावी रणनीति को जोड़कर एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरी, विशेष रूप से यादव समुदाय पर ध्यान केंद्रित करके, जो बिहार में सबसे बड़े और सबसे अधिक राजनीतिक रूप से मुखर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) समूहों में से एक है। लालू प्रसाद यादव, जो खुद यादव हैं, ने यादवों और मुसलमानों को एक साथ लाकर एक दुर्जेय जाति गठबंधन बनाया, जिसे एमवाई (मुस्लिम-यादव) गठबंधन के रूप में जाना जाता है। इस गठबंधन ने राजद को एक दशक से अधिक समय तक बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को नियंत्रित करने की अनुमति दी, जिसमें पिछड़ी जातियों और मुसलमानों के लिए सामाजिक न्याय पर जोर दिया गया। राजद की सफलता इस तथ्य पर टिकी थी कि जातिगत पहचान राजनीतिक वफादारी के लिए एक विश्वसनीय आधार प्रदान करता है।

दूसरी ओर, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडी(यू) भी जाति-आधारित लामबंदी के जरिए प्रमुखता में आया। हालांकि, लालू के विपरीत, नीतीश कुमार, जो एक कुर्मी (एक अन्य ओबीसी जाति) हैं, ने एक व्यापक रणनीति अपनाई, जिसमें गैर-यादव ओबीसी, दलित और उच्च जाति के मतदाताओं को शामिल करते हुए अधिक समावेशी जाति गठबंधन बनाने की कोशिश की गई। विकास, शासन और कानून व्यवस्था पर उनके फोकस ने उन्हें व्यापक समर्थन आधार बनाने में मदद की। जेडी(यू) ने उन जातियों को निशाना बनाया, जिन्हें आरजेडी ने बहिष्कृत महसूस किया इस समावेशी रणनीति ने नीतीश को बिहार में महत्वपूर्ण राजनीतिक पूंजी हासिल करने में मदद की, जिससे लालू की राजद के प्रभुत्व को चुनौती मिला।

2. **जातिगत गोलबंदी एवं वोट बैंक की राजनीति** - जातिगत गोलबंदी बिहार की चुनावी राजनीति की आधारशिला है, जिसमें राजनीतिक दल मतदाताओं को विश्वसनीय वोट बैंक बनाने के लिए जातिगत पहचान का स्पष्ट रूप से उपयोग करते हैं। संक्षेप में, जाति-आधारित वोट बैंक मतदाताओं का समूह है जो साझा जातिगत पहचान के कारण लगातार किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। यह रणनीति राजनीतिक दलों को विचारधारा या व्यापक नीति मंचों के आधार पर अपील किए बिना मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को आकर्षित करने में सक्षम बनाता है।

राजद की सफलता काफी हद तक यादवों और मुसलमानों को एक एकीकृत चुनावी ब्लॉक में संगठित करने की उसकी क्षमता पर निर्भर करती है। बिहार में संख्यात्मक रूप से प्रमुख समुदायों में से एक यादव, राजद की चुनावी ताकत का आधार रहे हैं। मुसलमानों के साथ गठबंधन करके, लालू प्रसाद यादव ने एक ऐसा गठबंधन बनाया जिसने न केवल चुनावी जीत सुनिश्चित की बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक-राजनीतिक ताकत का प्रतिनिधित्व भी किया जिसने बिहार की सत्ता की गतिशीलता को नया रूप दिया।

इसी तरह, जेडी(यू) की रणनीति एक वैकल्पिक वोट बैंक बनाने पर निर्भर रही है जिसमें गैर-यादव ओबीसी, दलित और महादलित शामिल हैं। इन जातियों को लक्षित करने वाली सामाजिक कल्याण नीतियों पर ध्यान केंद्रित करके और विकासोन्मुखी कार्यक्रम शुरू करके, नीतीश कुमार एक व्यापक-आधारित चुनावी गठबंधन बनाने में सक्षम थे जो सफलता के लिए किसी एक जाति समूह पर निर्भर नहीं था। इसके अतिरिक्त, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के साथ उनके गठबंधन, जिसका एक मजबूत उच्च-जाति समर्थन आधार है, ने जेडी(यू) की जाति-समावेशी राजनीतिक इकाई के रूप में स्थिति को और मजबूत किया।

3. **प्रमुख राजनीतिक नेता और उनकी जातियाँ** - बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर ऐसे नेताओं का दबदबा रहा है जिन्होंने अपनी जातिगत पहचान का इस्तेमाल करके मजबूत राजनीतिक आधार बनाया है, नेतृत्व के पदों पर पहुँचने के लिए अपने जातिगत नेटवर्क पर भरोसा किया है। बिहार के दो सबसे प्रमुख नेता- लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार- जाति और राजनीतिक नेतृत्व के बीच जटिल संबंध को दर्शाते हैं।

- **लालू प्रसाद यादव** - लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक प्रमुखता में वृद्धि उनकी यादव पहचान में गहराई से निहित है, जो बिहार में सबसे अधिक आबादी वाले और राजनीतिक रूप से मुखर ओबीसी समूहों में से एक है। लालू बिहार में ओबीसी सशक्तिकरण का प्रतीक बन गए, खासकर मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बाद, जिसने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण की सिफारिश की। वह यादवों के समर्थन को मजबूत करने में सक्षम थे, जो राज्य में एक महत्वपूर्ण चुनावी ब्लॉक बनाते हैं, और इसे मुस्लिम वोट के साथ मिलाकर एमवाई (मुस्लिम-यादव) गठबंधन बनाते हैं। इस सामाजिक गठबंधन ने लालू को 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में बिहार की राजनीति पर हावी होने में सक्षम बनाया। उनकी नेतृत्व शैली की विशेषता पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक न्याय पर ध्यान केंद्रित करना था, लेकिन उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अक्षमताओं के आरोप भी लगे।
- **नीतीश कुमार** - नीतीश कुमार का नेतृत्व प्रक्षेपवक्र उनकी कुर्मी पहचान से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो बिहार में एक और महत्वपूर्ण ओबीसी समूह है। हालांकि, लालू के विपरीत, नीतीश ने अधिक समावेशी राजनीतिक रणनीति अपनाई। उन्होंने शासन, विकास और कानून व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करके अपना आधार बढ़ाया, जिससे गैर-यादव ओबीसी, ईबीसी और दलितों सहित कई जातियों का समर्थन मिला। सुशासन पर नीतीश के जोर ने उन्हें लालू की जाति-केंद्रित राजनीति से अलग खड़ा करने में मदद की और उन्होंने जातिगत सीमाओं को पार करते हुए एक व्यापक गठबंधन बनाने में सफलता पाई। महादलितों जैसे छोटे जाति समूहों को अपने राजनीतिक पाले में एकीकृत करने की नीतीश की क्षमता बिहार में उनके निरंतर नेतृत्व में प्रमुख कारकों में से एक रहा है।
- **रामविलास पासवान** - बिहार के एक महत्वपूर्ण दलित नेता, रामविलास पासवान ने दलित मुद्दों को राज्य की राजनीति में सबसे आगे लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दुसाध समुदाय से आने वाले पासवान ने अपनी जातिगत पहचान का इस्तेमाल एक मजबूत दलित मतदाता आधार बनाने के लिए किया। उनकी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (LJP), बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में दलित हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अन्य नेताओं की तरह, पासवान की राजनीतिक रणनीति में बिहार की चुनावी राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए भाजपा जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करना शामिल था।

इन नेताओं ने अपने-अपने जातिगत आधारों को रणनीतिक रूप से संगठित करके अपने राजनीतिक करियर का निर्माण किया है, जबकि जीतने वाले चुनावी गठबंधन बनाने के लिए अन्य समूहों के साथ गठबंधन बनाने का प्रयास किया है।

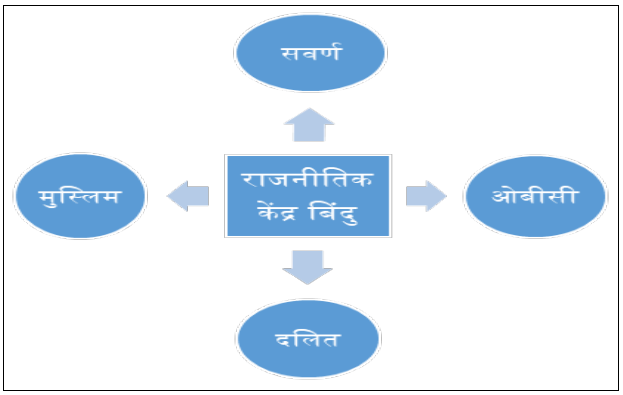

4. **मुख्य जाति ब्लॉक (वोट बैंक)** - वोट बैंक, खास तौर पर जाति आधारित, बिहार में चुनावी राजनीति के लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। राज्य में राजनीतिक दल समर्थन के लिए खास जाति समूहों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं, जो चुनावी नतीजों को काफी हद तक प्रभावित करते हैं।

- **यादव** - सबसे बड़े ओबीसी समूहों में से एक के रूप में, यादव आरजेडी के प्राथमिक वोट बैंक रहे हैं। उनकी मजबूत संख्यात्मक उपस्थिति और लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व के साथ उनके जुड़ाव ने उन्हें पार्टी की चुनावी रणनीति का केंद्र बना दिया है।

- **कुर्मी** - नीतीश कुमार की जेडी(यू) को कुर्मी जाति से काफी समर्थन मिलता है, जो एक छोटा लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली ओबीसी समूह है। नीतीश की जातिगत पहचान और उनके विकासोन्मुखी शासन मॉडल ने कुर्मियों को जेडी(यू) के चुनावी आधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया है।
- **दलित** - दलित, खास तौर पर महादलित, हाल के वर्षों में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक बन गए हैं। नीतीश कुमार की लक्षित कल्याणकारी नीतियों और महादलितों को सशक्त बनाने के प्रयासों ने उन्हें इस समुदाय से पर्याप्त समर्थन दिलाया है, जिससे वे उनके राजनीतिक गठबंधन का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं।
- **मुस्लिम** - बिहार में महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक मुस्लिम, पारंपरिक रूप से राजद जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ जुड़े रहे हैं। राजद का एमवाई (मुस्लिम-यादव) गठबंधन सुनिश्चित करता है कि पार्टी को मुस्लिम समर्थन मिले, खासकर भाजपा के उदय के साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के संदर्भ में।

5. **आरक्षण और जाति प्रतिनिधित्व** - भारत में आरक्षण नीतियों, खासकर 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद लागू की गई नीतियों ने बिहार की चुनावी राजनीति और जाति प्रतिनिधित्व को काफी प्रभावित किया है। मंडल आयोग ने ओबीसी के लिए 27% सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक सीटों के आरक्षण की सिफारिश की, जिसने बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में राजनीतिक लामबंदी की लहर शुरू कर दी। इस नीति ने राज्य के राजनीतिक संस्थानों में ओबीसी प्रतिनिधित्व को बढ़ाकर राजनीतिक परिदृश्य को गहराई से बदल दिया, जो पहले उच्च जातियों के वर्चस्व में था।

बिहार में, आरक्षण नीतियों ने ओबीसी को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने में मदद की, जिससे नेतृत्व उच्च जातियों से पिछड़ी जातियों में स्थानांतरित हो गया। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का उदय इन नीतियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। दोनों नेता ओबीसी समुदायों से हैं और आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन के बाद ओबीसी की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी से लाभान्वित हुए हैं। जाति-आधारित आरक्षण ने राजनीतिक प्रक्रिया में अधिक समावेश की सुविधा प्रदान की है, ओबीसी और दलित अब बिहार की शासन संरचनाओं में केंद्रीय भूमिका निभा रहे हैं।

आरक्षण ने बिहार के राजनीतिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों (एससी) के प्रतिनिधित्व को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। दलित समुदायों से ताल्लुक रखने वाले रामविलास पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं ने आरक्षण नीतियों से प्रेरित दलितों के बीच बढ़ती राजनीतिक चेतना के कारण राजनीतिक प्रमुखता हासिल की है। नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई महादलित जैसी उप-श्रेणियों के निर्माण ने सबसे अधिक हाशिए पर पड़े समूहों के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दायरे को और व्यापक बना दिया है।

बदलते जातिगत समीकरण

1. **मंडल के बाद सत्ता की गतिशीलता में बदलाव और समकालीन बिहार की राजनीति पर इसका प्रभाव**- 1990 में लागू की गई मंडल आयोग की रिपोर्ट ने पूरे भारत में राजनीतिक परिदृश्य को नाटकीय रूप से बदल दिया, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां जातिगत पदानुक्रम गहराई से जड़ जमाए हुए थे। आयोग ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण की सिफारिश की, जिसने इन समूहों के बीच महत्वपूर्ण राजनीतिक लामबंदी को बढ़ावा दिया। इस अवधि को मंडल युग के रूप में जाना जाता है, जिसने ओबीसी, विशेष रूप से यादव और कुर्मी जातियों को सशक्त बनाकर बिहार की जाति और राजनीतिक गतिशीलता को नया रूप दिया और राज्य की राजनीति में उच्च-जाति के प्रभुत्व को कम करने में योगदान दिया।

मंडल के बाद के दौर में बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं का उदय हुआ, जिन्होंने चुनावी प्रभुत्व हासिल करने के लिए ओबीसी के नए राजनीतिक सशक्तीकरण का लाभ उठाया। लालू की सामाजिक न्याय की राजनीति, जो जाति-आधारित लामबंदी पर केंद्रित थी, मंडल आयोग द्वारा लाए गए सामाजिक-राजनीतिक परिवर्तनों की सीधी प्रतिक्रिया थी। मुस्लिम समुदाय के साथ गठबंधन करके, लालू ने एमवाई (मुस्लिम-यादव) गठबंधन बनाया, जिसने 1990 के दशक और 2000 के दशक की शुरुआत में उनकी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लिए एक विश्वसनीय वोट बैंक बनाया। इस गठबंधन ने पारंपरिक उच्च-जाति के कुलीनों से सत्ता को पिछड़ी जातियों, खासकर यादवों में स्थानांतरित करके बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को मौलिक रूप से बदल दिया।

मंडल आयोग के प्रभाव ने नई जाति-आधारित पार्टियों और नेताओं के उदय को भी जन्म दिया, जिसमें जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी(यू)] के नीतीश कुमार भी शामिल हैं। कुर्मी नेता के रूप में, नीतीश यादवों से अलग ओबीसी आबादी के एक अन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, और उन्होंने खुद को लालू की यादव-प्रभुत्व वाली आरजेडी के प्रति संतुलन के रूप में स्थापित किया। समावेशी शासन और विकास पर नीतीश का ध्यान, साथ ही गैर-यादव ओबीसी और अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए उनकी वकालत ने उन्हें एक व्यापक-आधारित राजनीतिक गठबंधन बनाने की अनुमति दी, जो मंडल युग की जाति की राजनीति से परे था। उनका उदय मंडल के बाद के बिहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि जाति की पहचान महत्वपूर्ण बना रहा, लेकिन शासन और विकास ने राजनीतिक विमर्श में एक बड़ी भूमिका निभाना शुरू कर दिया।

समकालीन बिहार में, मंडल आयोग का प्रभाव राजनीतिक गतिशीलता को आकार देना जारी रखता है, लेकिन सख्त जाति-आधारित सत्ता संरचनाएं धीरे-धीरे विकसित हो रहा हैं। मंडल रिपोर्ट के कार्यान्वयन ने ओबीसी और दलितों के लिए राजनीतिक स्थान खोला, और जबकि बिहार की राजनीति में जाति एक शक्तिशाली कारक बना हुआ है, नए गठबंधन और बदलती सामाजिक अपेक्षाओं ने मतदाता व्यवहार को फिर से आकार देना शुरू कर दिया है।

2. **नए गठबंधन और मतदान पैटर्न में बदलाव: बिहार की राजनीति में हालिया रुझान** - बिहार के जाति समीकरणों में सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गैर-यादव ओबीसी और अन्य हाशिए पर पड़े जाति समूहों को आकर्षित करने की क्षमता रही है, एक ऐसा कदम जिसने राज्य की पारंपरिक वोट-बैंक राजनीति को बदल दिया है। ऐतिहासिक रूप से, भाजपा को एक उच्च जाति की पार्टी के रूप में देखा जाता था, जिसकी ओबीसी और दलितों के बीच सीमित अपील थी। हालाँकि, हाल के वर्षों में, पार्टी ने अपने मतदाता आधार का विस्तार करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं, विशेष रूप से गैर-यादव ओबीसी को लक्षित करके, जो लालू प्रसाद यादव के तहत राजद के प्रभुत्व से बाहर महसूस करते थे। भाजपा की रणनीति में उन जाति समूहों की पहचान करना शामिल था जो लालू के यादव-केंद्रित राजनीतिक मंच का हिस्सा नहीं थे। कुर्मी, कोइरी और ईबीसी जैसे इन समूहों पर ध्यान केंद्रित करके भाजपा ने बिहार के जाति-आधारित राजनीतिक पारिस्थितिकी तंत्र में अपने लिए सफलतापूर्वक जगह बनाई है। यह बदलाव 2014 और 2019 के राष्ट्रीय चुनावों में स्पष्ट था, जहाँ भाजपा ओबीसी और दलितों से महत्वपूर्ण समर्थन हासिल करने में सफल रही, जिससे पार्टी को बिहार की राजनीति में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित होने में मदद मिली।

इसके अलावा, भाजपा और नीतीश कुमार की जेडी(यू) के बीच गठबंधन ने गैर-यादव ओबीसी और उच्च जातियों के बीच भाजपा की अपील को और मजबूत किया। कुर्मी और ईबीसी के बीच अपने मजबूत समर्थन आधार के साथ नीतीश ने भाजपा के उच्च-जाति समर्थन को पूरक बनाया, जिससे गठबंधन को राजद के एमवाई गठबंधन के लिए एक व्यापक-आधारित विकल्प पेश करने की अनुमति मिली। इस साझेदारी ने भाजपा-जेडी(यू) गठबंधन को चुनावी सफलता हासिल करने में मदद की है, जैसा कि 2005, 2010 और 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों में देखा गया है।

बिहार की राजनीति में एक और महत्वपूर्ण प्रवृत्ति जाति और धार्मिक पहचान के आधार पर गठबंधनों का पुनर्मूल्यांकन है। जबकि राजद का एमवाई गठबंधन एक मजबूत चुनावी ताकत बना हुआ है, खासकर मुसलमानों और यादवों के बीच, नए गठबंधनों ने इसके प्रभुत्व को चुनौती देना शुरू कर दिया है। उदाहरण के लिए, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का राजद के नेता के रूप में उभरना पार्टी को आधुनिक बनाने और पारंपरिक मुस्लिम-यादव वोट बैंक से परे अपनी अपील का विस्तार करने के प्रयास का संकेत देता है। तेजस्वी ने केवल जाति-आधारित राजनीति पर निर्भर रहने के बजाय बेरोजगारी और आर्थिक विकास जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके दलितों और ईबीसी सहित अन्य हाशिए के समूहों को आकर्षित करने की कोशिश की है।

नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीतियाँ भी इन बदलते जाति समीकरणों को प्रतिबिंबित करने के लिए विकसित हुई हैं। दलित समुदाय के भीतर एक अलग महादलित श्रेणी बनाने के उनके प्रयास - जो सबसे अधिक हाशिए पर पड़े दलितों का प्रतिनिधित्व करते हैं - उन समूहों तक पहुँचने के उनके प्रयासों को प्रदर्शित करता है जो व्यापक राजनीतिक विमर्श से अलग-थलग महसूस करते हैं। इस दृष्टिकोण ने नीतीश को एक विविध मतदाता आधार

बनाने की अनुमति दी है जिसमें न केवल कुर्मी और ईबीसी शामिल हैं, बल्कि दलितों और महादलितों के महत्वपूर्ण वर्ग भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पसमांदा मुसलमानों (पिछड़ी जाति के मुसलमानों) तक भाजपा की पहुँच बिहार के मतदान पैटर्न में एक और बदलाव को दर्शाती है। ऐतिहासिक रूप से, बिहार में मुसलमानों ने राजद जैसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का भारी समर्थन किया है। हालाँकि, मुस्लिम समुदाय के भीतर सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित वर्गों से अपील करके, भाजपा ने पारंपरिक मुस्लिम वोट आधार को विभाजित करने का प्रयास किया है, जिससे राज्य की जाति और सांप्रदायिक गतिशीलता और भी जटिल हो गई है।

समकालीन रुझान और भविष्य का दृष्टिकोण

1. **युवा, सोशल मीडिया और बदलती जातिगत गतिशीलता का प्रभाव** - हाल के वर्षों में, बिहार का राजनीतिक परिदृश्य नए सामाजिक घटनाक्रमों, विशेष रूप से चुनावों में युवाओं और सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका से प्रभावित हुआ है। बिहार की 58% से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए युवा जनसांख्यिकी चुनाव परिणामों को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण कारक बन गई है। इस बदलाव के कारण विकास-केंद्रित राजनीति, आर्थिक अवसरों और रोजगार की बढ़ती मांग हुई है, जो धीरे-धीरे पारंपरिक जाति-आधारित राजनीति के प्रभुत्व को खत्म कर सकती है।

सोशल मीडिया ने बिहार में राजनीतिक अभियानों को भी बदल दिया है, जिससे पार्टियों को अधिक संवादात्मक तरीके से मतदाताओं से सीधे जुड़ने में मदद मिली है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव जैसे नेताओं ने अपने संदेशों को संप्रेषित करने के लिए ट्विटर और फेसबुक जैसे प्लेटफार्मों का उपयोग किया है, खासकर युवा मतदाताओं तक, जो अतीत की जाति-आधारित राजनीति से खुद को नहीं जोड़ सकते हैं। सोशल मीडिया ने राजनेताओं को केवल जाति गठबंधनों पर निर्भर रहने के बजाय शासन, विकास और भ्रष्टाचार के इर्द-गिर्द आख्यान गढ़ने की अनुमति द है। इस बदलाव का लोकतांत्रिक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि यह पारंपरिक अभिजात वर्ग से परे की आवाज़ों को राजनीतिक चर्चा में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

एक और बड़ा विकास जातिगत गतिशीलता का निरंतर विकास है। जबकि जाति एक शक्तिशाली शक्ति बना हुआ है, इसकी भूमिका अधिक जटिल और बहुआयामी होती जा रही है। राजनीतिक दल तेजी से इस बात से अवगत हो रहे हैं कि केवल एक जाति समूह को पूरा करना अब चुनाव जीतने के लिए पर्याप्त नहीं है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पारंपरिक मुस्लिम-यादव (एमवाई) गठबंधन में कुछ विखंडन देखा गया है क्योंकि पार्टी दलितों और अत्यंत पिछड़ी जातियों (ईबीसी) सहित अन्य हाशिए के समूहों तक पहुँचने की कोशिश करती है। इसी तरह, नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) [जेडी (यू)] ने गैर-यादव ओबीसी, दलितों और महादलितों के बीच अपने आधार को मजबूत करने की कोशिश की है, यह मानते हुए कि चुनावी सफलता के लिए एक व्यापक गठबंधन आवश्यक है।

2. **जाति-तटस्थ राजनीति का उदय**- इस बात पर बहस बढ़ रही है कि क्या बिहार जाति-तटस्थ राजनीति की ओर बढ़ रहा है, जहाँ शासन और विकास जाति-आधारित लामबंदी पर प्राथमिकता लेते हैं। हालाँकि जाति की राजनीति का प्रभुत्व निर्विवाद रूप से कमज़ोर हो गया है, लेकिन यह दावा करना जल्दबाजी होगी कि बिहार की राजनीति पूरी तरह से जाति-तटस्थ है। जाति की पहचान अभी भी मतदाता व्यवहार को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और राजनीतिक दल जाति के अंकगणित के आधार पर गठबंधन बनाना जारी रखते हैं।

हालाँकि, मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार के कार्यकाल की विशेषता जाति-तटस्थ शासन को बढ़ावा देने के प्रयासों से रही है। विकास, कानून और व्यवस्था और बुनियादी ढाँचे में सुधार पर कुमार के ध्यान ने कई जाति समूहों से समर्थन प्राप्त किया है। उनके प्रशासन ने हाशिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देश्य से कई कार्यक्रम शुरू किए, जैसे कि महादलित श्रेणी, जिसने सबसे अधिक सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित दलितों को लक्षित किया। ये नीतियाँ जातिगत विभाजन को पार करने के प्रयास को दर्शाती हैं, जिसमें शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो सभी समूहों को लाभान्वित करते हैं, चाहे उनकी जाति संबद्धता कुछ भी हो।

भाजपा ने उच्च जातियों के बीच अपने पारंपरिक समर्थन से परे अपने मतदाता आधार का विस्तार करके अधिक जाति-तटस्थ राजनीतिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का भी प्रयास किया है। हाल के वर्षों में, भाजपा ने राष्ट्रवाद,

विकास और प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और स्वच्छ भारत अभियान जैसी कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देकर गैर-यादव ओबीसी और दलितों को आकर्षित करने का काम किया है, जिन्हें सभी नागरिकों को समान रूप से लाभान्वित करने के रूप में तैयार किया गया है। जबकि ये प्रयास शासन-केंद्रित राजनीति की ओर बदलाव का संकेत देते हैं, जाति-आधारित गठबंधन चुनावी रणनीतियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहते हैं। साथ ही, यह स्वीकार करना आवश्यक है कि जाति-तटस्थ राजनीति का मतलब जाति संबंधी विचारों का पूरी तरह से गायब होना नहीं हो सकता है। इसके बजाय, यह जाति की अधिक सूक्ष्म समझ की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जहाँ जाति की पहचान विकास और शासन के मुद्दों के साथ सह-अस्तित्व में है। यह परिवर्तन धीरे-धीरे होने की संभावना है, क्योंकि जाति बिहार के सामाजिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग और राजनीतिक लामबंदी का एक साधन बना हुआ है।

3. **जाति-आधारित राजनीति का भविष्य** - बिहार में जाति-आधारित राजनीति का भविष्य दो प्रमुख प्रक्षेपवक्रों के साथ विकसित होने की संभावना है। सबसे पहले, विकास और शासन पर जोर बढ़ रहा है, जैसा कि राजनीतिक अभियानों के बदलते फोकस से स्पष्ट है। युवा मतदाता, विशेष रूप से, जाति की पहचान से कम चिंतित हैं और बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। यह प्रवृत्ति बताती है कि भविष्य के राजनीतिक दलों को जाति-आधारित लामबंदी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय, जातिगत रेखाओं के पार मतदाताओं को ठोस लाभ पहुँचाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी।

दूसरा, जातिगत गठबंधनों की तरलता बिहार की राजनीति के भविष्य को आकार देने में भूमिका निभाती रहेगी। जबकि पारंपरिक जातिगत गठबंधन जैसे कि एमवाई गठबंधन महत्वपूर्ण बने हुए हैं, वे कम कठोर होने की संभावना है क्योंकि राजनीतिक दल कई जाति समूहों को शामिल करते हुए व्यापक गठबंधन बनाने की कोशिश करते हैं। यह प्रवृत्ति जेडी(यू) और बीजेपी जैसी पार्टियों की गठबंधन-निर्माण रणनीतियों में पहले ही देखी जा चुकी है, जिन्होंने गैर-यादव ओबीसी, दलितों और ईबीसी तक अपनी अपील का विस्तार किया है। ऐसे गठबंधनों की सफलता जातिगत पहचान को शासन और विकास के मुद्दों के साथ संतुलित करने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी।

हालांकि, यह संभावना नहीं है कि बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से जातिगत राजनीति पूरी तरह से गायब हो जाएगा। जाति एक गहरी अंतर्निहित सामाजिक संस्था बना हुआ है, और राजनीतिक दल कुछ हद तक जाति-आधारित संरक्षण नेटवर्क पर निर्भर रहना जारी रखेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहाँ जातिगत पहचान अक्सर अधिक स्पष्ट होता है, जाति-आधारित राजनीति बनी रहने की संभावना है। इसलिए, जबकि जाति की राजनीति शासन और विकास के मुद्दों को शामिल करने के लिए विकसित हो सकती है, यह निकट भविष्य में बिहार में चुनावी नतीजों को आकार देना जारी रखेगें।

सुझाव

राजनीतिक जीवन में जाति-आधारित विभाजन को कम करने और समावेशी शासन को बढ़ावा देने के लिए सुझाव

- **जाति-तटस्थ नीतियों को बढ़ावा दें** - जाति-आधारित विभाजन को कम करने का एक तरीका ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना है जो जाति की परवाह किए बिना सभी नागरिकों को समान रूप से लाभान्वित करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित विकास कार्यक्रमों को जातिगत रेखाओं के पार समाज के सबसे हाशिए पर पड़े वर्गों तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए। इससे जाति-आधारित संरक्षण से ध्यान हटाकर समावेशी शासन की ओर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी।
- **शैक्षणिक और रोजगार के अवसरों को मजबूत करें** - राजनीति में जाति के प्रभाव को कम करने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक समान पहुँच प्रदान करना महत्वपूर्ण है। कौशल विकास और रोजगार सृजन के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने से आर्थिक और सामाजिक गतिशीलता के लिए जाति नेटवर्क पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे जातिगत पहचान का राजनीतिक महत्व कम हो सकता है।
- **अंतर-जातीय गठबंधनों को बढ़ावा दें** - राजनीतिक दलों को एकल-जाति समर्थन आधारों से परे समावेशी गठबंधन बनाने के लिए प्रोत्साहित करना जाति-आधारित ध्रुवीकरण को कम करने में मदद कर सकता

है। अंतर-जातीय गठबंधनों को बढ़ावा देने और शासन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके, राजनीतिक दल अधिक सामंजस्यपूर्ण राजनीतिक माहौल में योगदान दे सकते हैं।

- **सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करें** - अधिक समतावादी समाज बनाने के लिए विभिन्न जाति समूहों के बीच सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करना आवश्यक है। सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों को मजबूत किया जाना चाहिए जो सबसे अधिक हाशिए पर पड़े वर्गों, जैसे कि ईबीसी और महादलितों पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक और सामाजिक लाभ उन लोगों तक पहुँचें जिन्हें उनकी सबसे अधिक आवश्यकता है।

शासन-केंद्रित राजनीति की ओर हाल के रुझानों के बावजूद, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में जाति एक स्थायी शक्ति बना हुआ है। जाति की पहचान मतदाता व्यवहार को आकार देना जारी रखता है, और राजनीतिक दल अभी भी चुनाव जीतने के लिए जाति-आधारित गठबंधनों पर निर्भर हैं। हालाँकि, युवाओं, सोशल मीडिया और विकास-केंद्रित शासन की बढ़ती भूमिका यह संकेत देती है कि बिहार का राजनीतिक परिदृश्य धीरे-धीरे विकसित हो रहा है। जबकि जाति की राजनीति पूरी तरह से गायब होने की संभावना नहीं है, यह अधिक सूक्ष्म होने की संभावना है, जिसमें राजनीतिक दल जाति संबंधी विचारों को शासन और विकास के मुद्दों के साथ संतुलित करेंगे।

निष्कर्ष

जाति बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक कारक रही है, जिसने चुनावी रणनीतियों, पार्टी गठबंधनों और नेतृत्व की गतिशीलता को आकार दिया है। ऐतिहासिक रूप से, बिहार में राजनीति पर उच्च जाति के अभिजात वर्ग का वर्चस्व था, लेकिन 1990 के दशक में मंडल आयोग के कार्यान्वयन ने ओबीसी और दलितों को सशक्त बनाया, जिससे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे नेताओं का उदय हुआ। मंडल के बाद के युग में सत्ता की गतिशीलता में बदलाव देखा गया, जिसमें जाति-आधारित पार्टियाँ महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकतों के रूप में उभरा। लालू जैसे नेताओं ने जाति और धर्म के आधार पर गठबंधन बनाए, जैसे मुस्लिम-यादव (एमवाई) गठबंधन, जबकि नीतीश कुमार ने गैर-यादव ओबीसी, ईबीसी और दलितों को आकर्षित करके व्यापक आधार बनाने की कोशिश किया।

समकालीन बिहार में, जबकि जाति एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बना हुआ है, नए विकास ने परिदृश्य को फिर से आकार देना शुरू कर दिया है। युवाओं की बढ़ती भूमिका, सोशल मीडिया और विकास-केंद्रित शासन की मांग ने पारंपरिक जाति-आधारित राजनीति को चुनौती देना शुरू कर दिया है। भाजपा और जेडी(यू) सहित राजनीतिक दलों ने शासन और विकास के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एकल-जाति गठबंधन से आगे बढ़कर व्यापक गठबंधन बनाकर अनुकूलन किया है।

संदर्भ

1. Biswas F, Khan N, Ahamed MF. A study of electoral dynamic and voting behavior from 2004 to 2019 Lok Sabha elections of West Bengal. GeoJournal. 2021;1:1-27.
2. Buttimer A, Seamon D. The human experience of space and place. Routledge, 2015.
3. Chandra K. Patronage, democracy, and ethnic politics in India. In: Clientelism, social policy, and the quality of democracy, 2014, p. 135-72.
4. Chatterjee P. Classes, capital and Indian democracy. Economic and Political Weekly. 2008;43:89-93.
5. Coakley J. Society and political culture. In: Politics in the Republic of Ireland. London: Routledge, 2017, p. 30-56.
6. Desai S, Temsah G. Muslim and Hindu women's public and private behaviors: Gender, family, and communalized politics in India. Demography. 2014;51(6):2307-2332.
7. Jaffrelot C. India’s silent revolution: The rise of the lower castes in North India. C. Hurst & Co. Publishers, 2003.
8. Kumar R. Identity politics and the contemporary Indian feminist movement. In: Routledge, 2019, p. 274-92.
9. Kumar S, Alam MS, Joshi D. Caste dynamics and political process in Bihar. Journal of Indian School of Political Economy. 2008;20(1):1-32.
10. Kumar S. Post-Mandal politics in Bihar: Changing electoral patterns. New Delhi: SAGE Publications India Pvt. Ltd, 2018.
11. Kumar S. Understanding backward caste movement in contemporary Bihar. The Routledge India, 2022.

12. RajKishor. Understanding the politics of Bihar. Indian History Congress. 2016;77:539-545.
13. Verma RK. Caste and Bihar politics. Economic and Political Weekly. 1991;26:1142-1144.
14. Witsoe J. Caste and democratization in postcolonial India: An ethnographic examination of lower caste politics in Bihar, 2011. Available from: https://doi.org/10.1080/13510347.2011.593327.